

पहले मुख्य समाचार।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी अभियान की शुरुआत।
- मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 12 हजार रुपए और सहायिकाओं का मानदेय 6 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने जारी किए आदेश।
- लखनऊ में शुरू हुआ दो दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव-दो हजार छब्बीस। पांच हजार एक सौ छानबे करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के किये गये एमओयू।
- बारिश तथा बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 26 जिलों में नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज नौवें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अभियान की शुरुआत करेंगी।

यह अभियान पूरे सितंबर माह में देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों और घरों में सामुदायिक भागीदारी के साथ संचालित किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के दस वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन, दीप प्रज्ज्वलन, लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित वीडियो प्रदर्शन तथा केंद्रीय मंत्री और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बीच संवाद प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित यह लेख आंगनबाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनबाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में राज्य स्तरीय समारोह में नव नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री योगी ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय आठ हजार रुपये से बढ़ाकर बारह हजार रुपये और सहायिकाओं का मानदेय चार हजार रुपये से बढ़ाकर छः हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की जाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और उनके परिवारों को हर वर्ष पांच लाख रुपये तक कैशलैस इलाज की सुविधा दिये जाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते नौ वर्षों में सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र स्मार्ट हो चुके हैं और इसमें काम करने वाली महिलाएं सम्मान जनक मानदेय प्राप्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र विकसित भारत की संकल्पना का आधार बनेंगे।

बचपन अगर सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो यही स्वस्थ बचपन एक समर्थ और स्वस्थ भारत की संकल्पना को पूरा करेगा और स्वस्थ और समर्थ भारत ही प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को पूरा करेगा जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत होगा। उसका आधार कोई बनने वाला है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बनने वाले हैं।

इस बीच, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2026 से प्रभावी होगा और इसका भुगतान अक्टूबर 2026 में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में दो दिवसीय यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव-दो हजार छब्बीस का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक वस्त्रोद्योग केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पहचान आज की नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि पिछले छः वर्षों में प्रदेश के वस्त्र परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में बढ़ोतरी हुई है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक 350 बिलियन यूएस डॉलर की टेक्सटाइल अपैरल इकोनॉमी और 100 बिलियन यूएस डॉलर के टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस राष्ट्रीय संकल्प में अपनी पूरी शक्ति के साथ भागीदारी कर सकें। पिछले 6 वर्ष में प्रदेश के वस्त्र, परिधान और हस्तशिल्प निर्यात में लगभग 56 फीसदी की यूपी के अंदर वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश इस सेक्टर में देश का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यूपी टेक मित्र पोर्टल लॉन्च करने के साथ हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में टेक्सटाइल सेक्टर में पांच हजार एक सौ छानवे करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्तावों के एमओयू किए गए। साथ ही एक सौ तिरसठ करोड़ रुपये के लेटर ऑफ कम्फर्ट और साठ करोड़ रुपये की सब्सिडी का वितरण किया गया।

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में कल डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में यूपी. स्टार्टअप संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम विचार से अवसर तक, नवाचार से निवेश तक और प्रतिभा से उपलब्धि तक की यात्रा को गति देने का एक प्रयास है।

बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के छब्बीस जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वहां बाढ़ की स्थिति बनी हुयी है। बहराइच में घाघरा नदी खतरे के निशान से बयालीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहां के बारह गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से इकतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सीतापुर के करीब दो सौ चौहत्तर गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं, फर्रुखाबाद में गंगा नदी की बाढ़ से एक सौ दो गांवों के करीब अस्सी हजार लोग प्रभावित हैं। प्रशासन ने बाढ़ और जलभराव वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से मौसम विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के पालन की अपील की है।

उधर, पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गयी। इसके चलते कई जिलों के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुयी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में बहराइच, बलरामपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती सहित कई जिलों के लिये वर्षा का अलर्ट जारी किया है।

प्रदेश भर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कानपुर देहात में जिला जज रविंद्र सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने कल हरी झंडी दिखाकर इससे संबंधित प्रचार वाहनों को रवाना किया। प्राधिकरण की सचिव नूपुर श्रीवास्तव ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराने की अपील की।

लोक अदालत में ऐसे वाद जैसे वैवाहिक वाद होते हैं, बैंक वसूली ऋण वाले मुकदमे होते हैं, बिजली के बिल, पानी के बिल और किसी भी तरीके के सिविल वाद या शमनीय वाद जो होते हैं जो सुलह समझौते से निपट सकते हैं उसके लिए बिना किसी अधिवक्ता शुल्क, बिना न्याय शुल्क के जनता सुबह 10 बजे से 5 बजे तक न्यायालय आ सकती है।

पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य रहे मोहसिन रजा को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया है। साथ ही आयोग के 08 सदस्य भी नामित किए गये हैं।
